उनके रख-रखाव के लिए प्रदान की है। इस मंत्रालय में राज्य राजकोष से राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चो का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ग)मध्य प्रदेश के वन विभाग से सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश में हाथी प्रदेश में हाथी अभयारण्य बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालय के कर्मचारी की हत्या

2287. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून ,1955 के "नवभारत टाइम्स" में मुंशी राम की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां , तो क्या सरकार ने हत्यारों की पहचान करने और उन्हें तत्काल पकड़ने के लिये किसी जांच दल का गठन किया है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि मुंशी राम की हत्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का ही नतीजा है;

(घ) इस हत्याकांड में अभी तक पुलिस द्वारा की गयी जांच के संबंध में पूर्ण ब्योरा क्या हैं; क्या सरकार जांच कार्रवाइयों से संतुष्ट है या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरों से मामले की जांच कराना चाहती है; और

(ड) इसका तथ्यात्मक ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ड) थाना नन्दी नगरी में 18 मार्च, 1995 को भा.द.सं की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था तथा दिल्ली में उत्तर- पूर्वी जिले के अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच पड़ताल शुरू कि गई ।

अब तक की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि मृत्तक विवेक विहार, दिल्ली के.स.स्वा सेवा औषधालय में चपरासी के रूप में कार्यरत था तथा पिछले 15 वर्षो से दिल्ली में अकेला हो रहा था । मृत्तक ने अपनी पत्नी , बच्चों तथा अपने नगर वाले खानदानी घर को कई वर्ष पहले ही छोड़ दिया था। बताया गया है कि मृतक अफीम का नशा करता था और चरित्रहीन था।

यद्यापि मृत्तक ने के स.स्वा.सेवा औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कुछ शिकायतें की थीं, लेकिन जांच पड़ताल में अब तक हत्या और जिस अधिकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है के बीच किसी प्रकार का संबंध सिद्ध होने के बारे में कोई पता नहीं चला हैं।

यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Capacity of ITl

2288. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the I.T.I. Ltd. set up in 1948 for producing equipments as required by the Department of Telecom (DOT) has now acquired capacity of annually producing about Rs. 3000 crores worth of telecom equipments;

(b) whether it is also a fact that the order book position of the I.T.I. Ltd. for the year 1995-96 is at a very low level of nearly 360 crores;

(c) if so, why the DOT has not placed adequate orders on the I.T.I. Ltd. for enabling it to achieve full capacity utilisation; and

(d) what specific steps Government propose to take for ensuring that the I.T.I. Ltd. will not turn "sick"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Production capacity is defined in terms of quantity of finished products. Since pricing of equipments is subject to the process of tendering, capacity of ITI in financial terms cannot be accurately quantified.

(b) For the year 1995-96, apart from the firm orders of about Rs. 430 crores at present LOI/APO's to the extent of about Rs. 560 crores are also available with ITI Ltd.

(c) and (d) Securing adequate orders and their suitable execution in the

competitive environment is the responsibility of the Management of ITI.

However, with a view to optimally utilising the capacity of its own PSUs viz. ITI & HTL as also to keep these PSUs commercially viable, DOT is following a policy under which 30 to 35% of DOT orders, for the items manufactured by these Companies, are kept reserved for them.

Simultaneously, government has also advised ITI to diversify their products and customers. Government also keeps a watch on the functioning of the Public sector Units and as and when necessary remedial action is taken for improving the health and productivity of the PSUs.

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी जेलों में यातनायें सहने वाले व्यक्तियों को पेंशन

2289. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की कोई योजना है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अविभजित भारत की जेलों जोकि अब पाकिस्तान में हैं, में यातनायें सहन की थीं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीति संबंधी इस मामले पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एस. सईद): (क) और (ख) विद्यमान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, बिना इस बात पर विचार किए कि देश विभाजन से पूर्व उन्होंने कहा जेल यातना भोगी थी, उन सभी भारतीय नागरिकों को कवर करती है जिन्होंने देश के स्वतंत्रताश संग्राम में भाग लिया था बशतें कि वे इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी करते हों और दस्तावेज प्रस्तुत करें।

Production of Crude Oil

2290.SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) production of crude oil presently from various oil wells in the Country;

(b) how much quantity of crude oil is produced annually from the Gujarat State oil wells;

(c) whether Government have asked for any foreign assistance for the production of crude oil; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) During the first quarter of this year (April 1995 to June 1995) the crude oil production was 8.860 MMT.

(b) The crude oil produced during 1994-95 in Gujarat was 6.279 MMT.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Inter Exchange Transfer of Telephones

2291. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the time usually taken in the transfer of telephones from one telephone exchange to another exchange;

(b) what are the stages involved in the transfer of telephones;

(c) whether it is a fact that as a result of inefficient handling, transfers of telephones are affected in as long as one year and the subscribers have to remind the officers at each stage;

(d) what steps Government propose to reduce the stages involved in the transfer of telephones with a view to avoid hardships to telephone subscribers; and

(e) what are the reasons that the responsibility is not fixed in cases of delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Sir, the norm for shifting of a working telephone from one exchange to another